ployees on the rolls of the company have been paid wages and salary upto November '98 on 10.12.98.

(b) to (d) Does not arise.

कोर सेक्टर में नकारात्मक विकास दर

2365. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 1998 के "द इकोनामिक टाइम्स" में "कोर सैक्टर पोस्ट्स नैगेटिव ग्रोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के विगत महीनों में मूल उद्योगों की विकास दर में भारी कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इन मूल उद्योग के उत्पादन में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी का अलग-अलग वर्तमान प्रतिशत क्या-क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) छः कोर सैक्टर का क्षेत्रवार तथा समग्र विकास निम्नानुसार है:—

आधार : 1993-94=100

(प्रतिशत परिवर्तन)

उद्योग	भार	1996-97	1997-98	1997-98 (अप्रैल-अक्तूबर)	1998-99 (अप्रैल-अक्तूबर)
कोयला	3.22	5.7	3.6	4.8	2.0
कच्चा तेल	4.17	-4.7	3.1	3.0	-3.7
विद्युत	10.17	3.8	6.5	6.9	6.3
इस्पात	5.13	5.7	3.5	6.6	-3.1
सीमेंट	1.99	9.6	9.1	7.4	2.7
पैट्रोलियम रिफाइनरी	2.00	7.0	3.6	5.0	2.3
समग्र	26.68	3.7	5.1	5.9	1.7

अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान छः अवसंरचना उद्योगों का समग्र विकास 17% है जबकि पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि के दौरान यह दर 5.9% थी। अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान विद्युत, सीमेंट, कोयला तथा पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में विकास सकारात्मक रहा है। तथापि, कच्चे तेल तथा इस्पात ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1998 के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अंश निम्नानुसार है:—

(प्रतिशत)

उद्योग	(सार्वजनिक क्षेत्र)	(निजी क्षेत्र)
कोयला	98.2	1.8
विद्युत उत्पादन	93.0	7.0
इस्पात	32.8	67.2
सीमेंट	3.7	96.3
पैट्रोलियम रिफाइनरी	100.0	—
कच्चा तेल	90.0	10.0

*वर्ष 1997-98 के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुटीर उद्योग क्षेत्र की स्थापना करना

2366. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र स्थापित करके कम निवेश पर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने की सम्भावना का पता लगाया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा

देने के लिए अभी तक कुछ प्रोत्साहन योजनाओं को कार्यान्वित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) जी हां।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अति लघु कुटीर क्षेत्र सहित, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन तथा विकास हेतु अवस्थापनापरक सुविधाओं का सृजन करने और प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनागत स्कीमें चला रहा है। इसके अतिरिक्त, लघु क्षेत्र उद्योग को प्रदान की गई सभी सुविधाएं तथा प्रोत्साहन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी उपलब्ध है।

लघु उद्योगों के लिए निगरानी व्यवस्था

2367. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के उन जिलों में जहां एक हजार से दो हजार लघु उद्योग हैं वहां विशेष निगरानी व्यवस्था कायम की जाएगी जो लघु उद्योगों की ऋण संबंधी समस्या पर ध्यान रखेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की निगरानी व्यवस्था किन-किन राज्यों के कितने-कितने जिलों में स्थापित की गई है और यह निगरानी व्यवस्था किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) बैंकों द्वारा लघु उद्योग एककों को वित्त पोषित करने की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरों पर पहले ही निगरानी प्रणालियां मौजूद हैं। राज्य स्तर पर "राज्य बैंकर समिति" द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण के प्रवाह की निगरानी की जाती है। और यह समिति लघु उद्योगों की ऋण से संबंधित समस्याओं को देखती है। जिला स्तर पर लघु एककों में ऋण के प्रवाह की निगरानी बैंकों की जिला समन्वय समिति द्वारा की जाती है।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा आधार वर्ष 1987-88 के आधार पर की गयी द्वितीय अखिल भारतीय पंजीकृत लघु उद्योग गणना के अनुसार, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय देश के 119 जिलों में से प्रत्येक में 1000—2000 पंजीकृत लघु उद्योग थे। इन 119 जिलों में से 39 में विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग बैंक शाखाएं चालू की गयी हैं। मार्च, 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक बैंकों को सलाह दी है कि वे और-अधिक विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग बैंक शाखाएं खोलने हेतु, केन्द्रों की पहचान करते समय, इन 80 जिलों में केन्द्रों का चुनाव करें।

उन राज्यों की सूची, जिलों की संख्या और उन के नाम सहित, अनुबंध के रूप में संलग्न की गयी है जहां 1000—2000 (द्वितीय अखिल भारतीय गणना के अनुसार) के बीच पंजीकृत लघु उद्योग हैं तथा जहां विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग शाखाएं खोली गयी हैं।

1000—2000 (द्वितीय अखिल भारतीय गणना के अनुसार) पंजीकृत लघु उद्योग वाले राज्य /जिले जहां विशेषज्ञता प्राप्त लघु उद्योग बैंक शाखाएं खोली गयी है।

क्र० सं०	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	विशाखापत्तम, वारंगल
2.	बिहार	1	सिंहभूम
3.	गुजरात	5	भावनगर, जामनगर, मेहंसाना, भारूच, जूनागढ़
4.	हरियाणा	1	सोनीपत
5.	कर्नाटक	3	तुपकुरू, कोलार, हसन
6.	केरल	2	कन्नौर, मालापुरम